

राजस्थान सरकार
कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर

क्रमांक-एफ 29/साप्र/प्रेस/2019-20/ 2068

दि 25-9-19

-- निविदा सूचना 1/2019-20 --

राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर के कार्यालय उपयोग हेतु बीमा/प्रावधानी निधि बैग्स की आपूर्ति की निविदा कराने हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकृत विभाग से पंजीकृत/रजिस्टर्ड फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सीज से सील बन्द लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

क्र०सं०	बीमा बैग्स एवं प्रावधानी निधि का विवरण/स्पेसिफिकेशन	अनुमानित मात्रा	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	बीमा बैग्स साईज 37X18 से.मी., 110 जीएसएम. लाईण्ड क्राफ्ट पेपर एवं इसके अतिरिक्त अच्छी गुणवत्ता का मलमल पर 2.50से.मी.अन्दर की ओर मुड़ा हुआ दोनों ओर 6 सेमी० बेली तथा नमूने के अनुसार मुद्रण।	70 हजार		
2	प्रावधानी निधि बैग्स साईज 37X18 से.मी., 110 जीएसएम.लाईण्ड क्राफ्ट पेपर एवं इसके अतिरिक्त अच्छी गुणवत्ता का मलमल पर 2.50से.मी.अन्दर की ओर मुड़ा हुआ दोनों ओर 6 सेमी० बेली तथा लाल पट्टी मुद्रण नमूने के अनुसार।	30 हजार	14000/- रु.	500/-रु.

- सम्बन्धित फर्म /कम्पनी / संस्था/एजेन्सीज को निर्धारित निविदा प्रपत्र दिनांक 09.10.2019 सांय 3.00 बजे तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रा० निधि विभाग, जयपुर के कार्यालय में दिनांक: 09.10.2019 सांय 2:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा से सम्बन्धित नियम, शर्तें निविदा प्रपत्र किसी भी कार्यालय दिवस में मुख्यालय कमरा न० 17 कैशियर के यहाँ राशि 500/-रु० जमा करवाकर प्राप्त कर सकते हैं या विभागीय वेब साइट www.sipf.rajasthan.gov.in, अथवा राज्य लोक उपापन पोर्टल (<http://sppp.raj.nic.in>) से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा पृथक से बैंक ड्राफ्ट निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा० निधि विभाग जयपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 10.10.2019 को प्रातः 11.00 बजे उपापन समिति द्वारा खोला जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
- निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार निदेशक/अति. निदेशक (प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि जयपुर को होगा।

अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन

राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर
निविदा प्रपत्र

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के कार्यालय उपयोग हेतु बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स मुद्रित/ तैयार करने का निविदा प्रपत्र

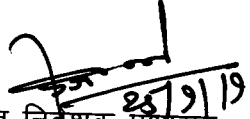
निविदा प्रपत्र का मूल्य 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र)

बिड प्रतिभूति 14,000/- (चौदह हजार रुपये मात्र)

नोट:-

- (1) इस निविदा प्रपत्र के साथ 'ए' से 'जी' परिशिष्ट संलग्न है।
 - 1 तकनीकी निविदा प्रपत्र - परिशिष्ट 'ई'
 - 2 वित्तीय निविदा प्रपत्र - परिशिष्ट 'एफ'
 - 3 निविदा की शर्तें - परिशिष्ट 'जी'
 - 4 अन्य परिशिष्ट ए से डी ।
- (2) निविदाएँ दो पृथक-पृथक लिफाफों में अलग-अलग तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करनी है।
- (3) तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ सील बंद लिफाफे में निम्न प्रपत्र दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है तथा सीलबंद लिफाफे पर "बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स मुद्रित/तैयार करने का निविदा प्रपत्र" अंकित करना होगा।
 - 1 फर्म/कम्पनी/संस्था/एजेन्सीज का पंजीयन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - 2 प्रतिभूति रुपये 14,000/- का बैंकर्स चेक/डी.डी. प्रस्तुत करना है।
 - 3 बिड निविदा शुल्क 500/- का बैंकर्स चेक/डी.डी./ रसीद संलग्न करनी होगी।
 - 4 फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज।
 - 5 जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।
 - 6 बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स साईज 37X18 सेमी. 110 जीएसएम लारेण्ड क्राफ्ट पेपर तथा अच्छी गुणवत्ता का मलमल पर 2.50 सेमी. अन्दर की ओर मुड़ा हुआ दोनो ओर 6 सेमी बेली तथा लाल पट्टी मुद्रण नमूने के अनुसार बिना मुद्रण के 1-1 बैग तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- (4) जिन फर्मों/ठेकेदारों की तकनीकी निविदायें उपयुक्त पाई जायेगी उन्हीं फर्मों के वित्तीय प्रस्तावों की निविदाएं खोली जायेगी, अन्य फर्मों को अयोग्य माना जायेगा। वित्तीय निविदा प्रपत्र अलग लिफाफे में रखा जायेगा। इस लिफाफे पर वित्तीय निविदा अंकित करते हुए लिफाफे को सीलबंद किया जायेगा।
- (5) "तकनीकी निविदा" और "वित्तीय निविदा" के अलग अलग सीलबंद दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में रखकर उक्त बड़े लिफाफे को भी सीलबंद करना होगा तथा उक्त बड़े लिफाफे पर " बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स मुद्रित/तैयार करने का निविदा प्रपत्र " अंकित कर निर्धारित तिथि व समय तक जमा करना होगा। निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं होगा। डाक से प्राप्त निविदाएँ यदि निर्धारित दिनांक व समय पर नहीं पहुँचती है तो कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) दिनांक 09.10.2019 को सांय 03:00 बजे तक प्राप्त निविदाओं को दिनांक 10.10.2019 को प्रातः 11.00 बजे निविदाओं के लिफाफो को खोला जावेगा। इस हेतु गठित समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा। सक्षम पाये जाने पर उनकी वित्तीय निविदाएँ खोली जावेगी। बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स मुद्रित/तैयार करने की आपूर्ति की निविदा के फार्म, निविदा शर्तें सहित निविदा प्रकाशन तिथि से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में कैशियर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर कमरा नम्बर 17 में 500/- रुपये नकद भुगतान कर दिनांक 09.10.2019 सांय 2:00 बजे तक क्रय किये जा सकते हैं।


अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राज. जयपुर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मैंने/हमने जिन राजकीय विभाग / अर्द्धशासकी विभाग/संस्था में बीमा/प्रावधानी निधि बैग्स मुद्रित/तैयार करने की निविदा दी है, उनका/ मैं/ हम बोनाफाईड/ थोक विक्रेता/ सोल वितरक/ प्राधिकृत डीलर/ सोल सेलिंग/ विपणन एजेंट है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत का लिया जाएगा तथा निविदा का, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाये।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम
पूर्ण पता

टेलीफोन न० (निवास)
(कार्यालय)

राजस्थान सरकार
कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर मुख्यालय कार्यालय के उपयोग हेतु
बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स मुद्रित/तैयार करने का तकनीकी निविदा प्रपत्र

- 1 निविदादाता का नाम व पूर्ण पता :
- 2 निविदा सूचना क्रमांक :
- 3 निविदा शुल्क रूपयें 500/- :
जमा कराने का विवरण
- 4 निविदा प्रस्तुत करने की :
अंतिम तिथि एवं समय
- 5 बिड प्रतिभूति(अमानत) राशि का विवरण:
- 6 राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958/इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट
1932 के अन्तर्गत/इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर/
:.....
- 7 जीएसटी पंजीयन क्रमांक :
(नियमानुसार)
- 8 फर्म का पैन कार्ड नम्बर :

मुझे इस निविदा की संलग्न समस्त शर्तें मंजूर हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पूरा

राजस्थान सरकार

कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के कार्यालय उपयोग हेतु
बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स मुद्रित/तैयार करने की दरों का वित्तीय निविदा प्रपत्र

बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स मुद्रित/तैयार करने की दरें भरकर निविदादाता हस्ताक्षर करें तथा इस प्रपत्र को अलग लिफाफे में डालकर सील बन्द करें एवं लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "वित्तीय निविदा" अंकित करें। कार्य की दरें अंकों एवं शब्दों में अंकित करें।

क्र०सं०	बीमा बैग्स एवं बीमा पालिसी का विवरण/स्पेसिफिकेशन	अनुमानित मात्रा	दर-समस्त करों सहित (प्रति बैग/नग)
1	बीमा बैग्स साईज 37X18 से.मी., 110 जीएसएम. लाईण्ड काफ्ट पेपर एवं इसके अतिरिक्त अच्छी गुणवत्ता का मलमल पर 2.50से.मी. अन्दर की ओर मुड़ा हुआ दोनों ओर 6 सेमी० बेली तथा नमूने के अनुसार मुद्रण।	70 हजार	
2	प्रावधायी निधि बैग्स साईज 37X18 से.मी., 110 जीएसएम. लाईण्ड काफ्ट पेपर एवं इसके अतिरिक्त अच्छी गुणवत्ता का मलमल पर 2.50से.मी. अन्दर की ओर मुड़ा हुआ दोनों ओर 6 सेमी० बेली तथा लाल पट्टी मुद्रण नमूने के अनुसार।	30 हजार	

नोट:- बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स पर जो मुद्रण करवाया जाना है उसका नमूना/सैम्पल निविदा पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है उसके अनुसार ही दरें देनी होंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर नाम व
पूरा पता

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE DIRECTOR STATE INSURANCE & PROVIDENT
FUND DEPARTMENT JAISING HIGHWAY ROAD,
BANIPARK, JAIPUR**

परिशिष्ट 'जी'

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के कार्यालय उपयोग हेतु
बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स मुद्रित/तैयार करने की निविदा की शर्तें
निविदादाता को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदायें भेजते
समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

(अ) पात्रता (Eligibility Criteria) जो अनिवार्य है, के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी।

- 1- फर्म/कम्पनी/संस्था/एजेन्सीज का पंजियन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
- 2-निविदादाता को बिड प्रतिभूति रुपये 14,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रस्तुत करना होगा, जो निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के नाम होना चाहिये। बिड प्रतिभूति के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 3-निविदायें दो अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। प्रथम लिफाफा "प्रि-क्वालिफाइड बिड/तकनीकी बिड" का होगा तथा दूसरा "वित्तीय बिड" के लिये होगा। निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर कार्यालय में बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स आपूर्ति के लिये पृथक-पृथक बन्द लिफाफों में बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स आपूर्ति की वित्तीय निविदा प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 4-प्रथम लिफाफे (प्री क्वालिफिकेशन बिड/तकनीकी बिड) में निम्न प्रपत्र रखें जावेंगे:-
 - (क) फर्म/कम्पनी/संस्था/एजेन्सीज का पंजियन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - (ख) प्रतिभूति रुपये 14,000/- का बैंकर्स चैक/डी.डी. प्रस्तुत करना है।
 - (ग) बिड निविदा शुल्क 500/- का बैंकर्स चैक/डी.डी./ रसीद संलग्न करनी होगी।
 - (घ) फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज।
 - (ङ) जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।
- 5- दूसरे लिफाफे में केवल राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर कार्यालय उपयोग हेतु बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स मुद्रित/तैयार करने की वित्तीय बिड होगी जिसमें निविदादाता को अपनी दरें अंकों में एवं शब्दों में अंकित करनी होगी।
- 6- दोनों लिफाफे, तकनीकी बिड का सीलबंद लिफाफा तथा वित्तीय बिड का सीलबंद लिफाफा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के नाम होना चाहिए, साथ ही फर्म का नाम दूरभाष/मोबाइल नम्बर भी अंकित होना आवश्यक है।

(ब) सामान्य नियम व शर्तें :-

- 1-निविदा देनी वाली फर्म को बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स के नमूने मांगे जाने पर देने होंगे।
- 2-स्वीकृत दरों के अलावा अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
- 3-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व राज.लोक उपापन नियम 2013 की सभी शर्तों की पालना करनी होगी तथा बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स मुद्रित/तैयार करने की मात्रा/नमूने के अनुसार फर्म द्वारा समय पर आपूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि काटी जायेगी।
- 4-समस्त दरें स्याही से भरी होनी चाहिये। पेंसिल या अन्य वस्तुओं से भरी गयी दरों पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा बन्द एवं शील्ड लिफाफे में ही भेजी जानी चाहिये।
- 5-निविदा में दी गयी दर किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी। दरों का इन्द्राज अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी किया जाना आवश्यक है।

- 6- फर्म द्वारा बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स के संबंध में दिये गये आदेश / नमूने / मापदण्ड के अनुसार बैग्स की आपूर्ति नहीं करने पर किसी भी समय अनुबंध/आदेश को भंग किया जा सकता है।
- 7- विभाग किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्न दर वाली निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा को उसके कारणों को बताये बिना रद्द कर सकती है। निविदा द्वारा आमंत्रित की गई मात्रा या वस्तुओं में से प्रशासन के निर्णयानुसार उन सम्पूर्ण या आंशिक वस्तुओं या मात्रा के लिए आदेश दिये जा सकते हैं।
- 8- निविदादाता को संलग्न सभी प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित से प्रमाणित कर प्रस्तुत करने होंगे।
- 9- सर्वप्रथम तकनीकी बिड़ का लिफाफा खोला जावेगा, जिसकी उपापन समिति जाँच करेगी। जाँच के उपरान्त जो निविदादाता तकनीकी बिड़ में योग्य पाये जावेगे, उनकी ही वित्तीय बिड़ खोली जावेगी।
- 10- सफल निविदादाता को कार्य आदेश के जारी करने के सात दिवस में संविदा के 5 प्रतिशत की कार्य संपादन प्रतिभूति जमा करानी होगी तथा 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी दरें निरस्त कर दी जावेगी तथा बिड़ प्रतिभूति (अमानत) राशि जब्त कर दी जावेगी।
- 11- कार्य संपादन प्रतिभूति को संविदा की समाप्ति के दो माह बाद संतोषप्रद कार्य होने पर निविदादाता के लिखित रूप से आवेदन करने पर लौटाई जावेगी।
- 12- अनुबंधित फर्म बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स मुद्रित/तैयार करने का कार्य किसी दूसरी फर्म को सबलेट नहीं करेगा अगर अनुबंधित फर्म द्वारा सबलेट किया गया तो ठेका निरस्त कर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 13- न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर का होगा।
- 14- फर्म द्वारा आदेशानुसार बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स की आपूर्ति करने के पश्चात ही बिल भुगतान किया जायेगा वह बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।
- 15- बिल का भुगतान स्टोर अनुभाग से प्राप्त रिपोर्ट स्टॉक इन्द्राज के आधार पर किया जायेगा।
- 16- उक्त सामग्री हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक 09.10.2019 सायं 3 बजे तक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होंगी।
- 17- सफल निविदादाता द्वारा बीच में आपूर्ति छोड़ जाती है या कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 18- ठेके की अनुमोदित दरें स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी, जिसे 3 माह और बढ़ाया जा सकता है एवं आपसी सहमति से 3 माह और बढ़ाया जा सकता है। जिसके लिये फर्म के द्वारा दी गई दरों पर ही बीमा/प्रावधायी निधि बैग्स की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगी।
- 19- किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जिसे ठेकेदार को मानना होगा।
- 20- सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जयपुर होगा।
- 21- परिसमापित नुकसानी:- परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है : (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्तें ही लागू होंगी।)

(1)	(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2 ^{1/2} %
	(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए	5%
	(ग)	आधी अवधि से अवधि किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए	7 ^{1/2} %
	(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

23- पैनल्टी की राशि फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल/प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

24- यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
राज. जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पूरा पता.....

मोबाईल/टेलिफोन नं.....

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be a Conflict of Interest with one of more parties in a bidding process if, including but not limited to :
 - a. have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for
procurement of in response to their Notice Inviting
Bids No. Dated I/we hereby declare
under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is -----

The designation and address of the Second Appellate Authority is -----

1. Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved

:Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

5. Form of Appeal

- (a) **An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.**
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal

and proof of payment of fee.

- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6. Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of Appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply for by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan
Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. of
Before the(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

(Supported by an affidavit)

7. Prayer :

Place

Date

Appellant's Signature